



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. ५८६]

मई विस्तो, वृहस्पतिवार, दिसम्बर २९, १९८३/पौष ८, १९०५

No. ५८६]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 1983/PAUSA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वो छाती है जिससे इक यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, २९ दिसम्बर, १९८३

आदेश

का०आ० ९३७(अ)/१८कक/आई०डी०आर०ए०/८३ :—  
केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का०आ० १३४(अ)/१८कक/आई०डी०आर०ए०/७९ तारीख १३ मार्च, १९७९ द्वारा यथा उपांतरित आदेश सं. का०आ० ५२९(अ)/१८कक/आई०डी०आर०ए०/७४ तारीख ६ सितम्बर, १९७४ द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, बन्द रुण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को (जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कहा गया है) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स इंडिया बैलिंग एंड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर, पश्चिमी बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) तारीख ६ सितम्बर, १९७४ से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त अधिसूचित आदेश को उपयुक्त पांच वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रभावी बना रहना चाहिये और उसमें ३१ दिसम्बर, १९८३ तक की जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, अतिरिक्त अवधि के लिये इसे जारी रखने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये थे, (देखिए भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग सं. का०आ० ५१२(अ)/१८कक/आई०डी०आर०ए०/७९, तारीख ४ सितम्बर, १९७९, सं. का०आ० ७४९(अ)/१८कक/आई०डी०आर०ए०/८०, तारीख ५ सितम्बर, १९८०, और सं. का०आ० ६८४(अ)/१८कक/आई०डी०आर०ए०/८१, तारीख ४ सितम्बर, १९८१, सं. का०आ० १२५(अ)/१८कक/आई०डी०आर०ए०/८२, तारीख ५ मार्च, १९८२, सं. का०आ० ६४८(अ)/१८कक/आई०डी०आर०ए०/८२, तारीख ४ सितम्बर, १९८२, सं. का०आ० १५८(अ)/१८कक/आई०डी०आर०ए०/८३, तारीख ४ मार्च, १९८३ तथा सं. का०आ० ३८६(अ)/१८कक/आई०डी०आर०ए०/८३, तारीख ३१ मई, १९८३),

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त

प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, 30 जून, 1984 तक की और अवधि के लिये जारी रखा जाये,

अतः केन्द्रीय सरकार उच्चोग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उषा आवेदा 30 जून, 1984 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की और अवधि के लिये प्रभावी रहेगा।

[फा०सं० 2(14)/80-सौ०य०एस०]  
प्र०पी० सरकार, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th December, 1983

### ORDER

S.O. 937(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529 (E)|18AA|IDRA|74, dated the 6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134(E)|18AA|IDRA|79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs. India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of

five years from the 6th September, 1974;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983 (vide orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 512(E)|18AA|IDRA|79, dated the 4th September, 1979 S.O. 749(E)|18AA|IDRA|80, dated the 5th September, 1980, S.O. 684(E)|18AA|IDRA|81, dated the 4th September, 1981, S.O. 125(E)|18AA|IDRA|82, dated the 5th March, 1982, S.O. 648(E)|18AA|IDRA|82, dated the 4th September, 1982, S.O. 158(E)|18AA|IDRA|83, dated the 4th March, 1983, and S.O. 386(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for further period upto 30th June, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 30th June, 1984.

[File No. 2(14)|80-CUS]  
A. P. SARWAN, Jt. Secy.